I परिप्रेक्ष्य

भारतीय बैंकिंग प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) उच्च पूंजी अनुपात, बेहतर आस्ति गुणवत्ता और मजबूत आय वृद्धि के साथ मजबूत और समुत्थानशील बनी हुई हैं। इससे दो अंकीय ऋण वृद्धि और घरेलू आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिल रहा है। इस सुधार को बनाए रखने के लिए अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को और मजबूत करने और अतिरिक्त बफर बनाने की आवश्यकता है।

परिचय

I.1 वर्ष 2024 की ओर देखें तो, प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने संकेत दिया है कि मौद्रिक नीति सतर्क रहेगी क्योंकि मुद्रास्फीति में नरमी आने के बावजूद वह लक्ष्य से ऊपर है। इस परिस्थिति में, यद्यपि उच्च पूंजी बफर और प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) राहत प्रदान करते हैं, बैंकों को ऋण हानि से बचने की जरूरत है। विनियामकीय पूंजी और चलनिधि आवश्यकताओं के अलावा, गुणात्मक मापक, जैसे कि बेहतर प्रकटीकरण, मजबूत आचार संहिता और स्पष्ट अभिशासन संरचना वित्तीय स्थिरता की दिशा में योगदान देंगे।

I.2 हालांकि वैश्विक वातावरण संबंधी संभावना अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है, घरेलू आर्थिक गतिविधि के लिए संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई देती हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहतर आस्ति गुणवत्ता, उच्च पूंजी पर्याप्तता और मजबूत लाभप्रदता के साथ बेहतर होने के लिए अच्छी स्थिति में है। एनबीएफसी के वित्तीय संकेतक भी और मजबूत होने के लिए तैयार हैं, जो पर्याप्त पूंजी, बढ़े हुए प्रावधानों और बेहतर आस्ति गुणवत्ता से प्रेरित हैं। वित्तीय स्थिरता को कंपनियों की मजबूत वित्तीय स्थिति और उनके तुलनपत्रों के भार कम होने से बल मिल रहा है। इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और आगे की राह के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

बैंकों और गैर-बैंकों में गैर-जमानती उधार

I.3 हाल की अवधि में, गैर-जमानती खुदरा खंड की वृद्धि दर ने कुल बैंक ऋण वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। गैर-जमानती खुदरा ऋणों की आस्ति गुणवत्ता में अब तक कोई गिरावट नहीं देखी गई है। चुनिंदा उपभोक्ता क्रेडिट ऋणों और एनबीएफसी को बैंक ऋण के संबंध में नवंबर 2023 में घोषित किए गए सुविचारित और लक्षित मैक्रोप्रूडेंशियल उपाय सुरक्षात्मक स्वरूप के और वित्तीय स्थिरता के हित में हैं।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसीपी) मानदंडों की समीक्षा

I.4 वित्तीय प्रणाली में हो रहे घटनाक्रमों के साथ तालमेल रखने के लिए, रिज़र्व बैंक अपने विनियामकीय दृष्टिकोण को इकाई-आधारित से गतिविधि-आधारित में बदलने का प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के साथ, रिज़र्व बैंक की सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए अनुदेशों को सुसंगत बनाने हेतु वर्तमान आईआरएसीपी मानदंडों की व्यापक समीक्षा चल रही है।

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे की समीक्षा

I.5 7 जून 2019 से परिचालित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा, उधार देने वाली अधिकांश संस्थाओं के लिए एक सिद्धांत-आधारित स्थिर-स्थिति दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्राप्त अनुभव के आधार पर और सभी आरई में अनुदेशों को तर्कसंगत और सुसंगत बनाने के लिए इस ढांचे की

व्यापक समीक्षा चल रही है। इससे दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान को और गति मिलेगी।

अग्रिमों और निर्यात ऋण पर ब्याज दर संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

I.6 अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी मौजूदा विनियम विभिन्न आरई के लिए अलग-अलग हैं। बैंकों और अन्य आरई के लिए विनियामकीय ढांचे को सुसंगत बनाने के लिए मौजूदा विनियामकीय अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की गई है। इसके अलावा, हितधारकों की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण पर अनुदेशों की समीक्षा भी वर्तमान में चल रही है।

प्रत्याशित ऋण हानि (ईसीएल) आधारित ढांचे में अंतरण।

I.7 बैंकों द्वारा प्रावधान किए जाने के संबंध में ईसीएल ढांचा शुरू करने पर एक चर्चा पत्र (डीपी) 16 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, जिसमें हितधारकों से जानकारी मंगवाई गई थी। यद्यपि चर्चा पत्र के संबंध में प्राप्त जानकारी की जांच की जा रही है, कुछ तकनीकी पहलुओं पर समग्र रूप से जांच करने और स्वतंत्र इनपुट प्रदान करने के लिए एक बाहरी कार्य समूह - जिसमें शिक्षाविदों, उद्योग और चुनिंदा प्रमुख बैंकों के क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं - का गठन किया गया है। दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करते समय कार्य समूह की सिफारिशों को विधिवत शामिल किया जाएगा।

गैर-निधि आधारित सुविधाएं

I.8 गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाएं जैसे कि गारंटी, साख पत्र और सह-स्वीकृति (को-एक्सेपटेंस) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस खंड के व्यवस्थित और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी विनियमित इकाइयों पर लागू एनएफबी सुविधाओं को अधिशासित करने वाले विनियामकीय दिशानिर्देशों की एक व्यापक और स्व-निहित एकत्रित-सूची निर्धारित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, एनएफबी सुविधाओं पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा चल रही है।

दबावग्रस्त आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

I.9 जनवरी 2023 में, रिज़र्व बैंक ने बाजार प्रतिभागियों से टिप्पणियां मंगवाने के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया था। संरचना की नवीनता और जटिलता को देखते हुए, अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र जारी करने की दृष्टि से, वर्तमान में विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों की विस्तृत जांच चल रही है।

कनेक्टेड लेंडिंग के लिए ढांचा

I.10 उन व्यक्तियों को कनेक्टेड लेंडिंग करना या उधार देना जो एक ऋणदाता के निर्णय को नियंत्रित या प्रभावित करने की स्थिति में हैं, एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें मूल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन में समझौता किए जाने के नैतिक खतरे संबंधी मुद्दे शामिल हैं। इस मुद्दे पर मौजूदा दिशा-निर्देश सीमित दायरे में हैं और सभी आरई पर समान रूप से लागू नहीं हैं। इस मुद्दे के समाधान के लिए एक मसौदा परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा जिसमें कनेक्टेड लेंडिंग पर एकीकृत विनियामकीय ढांचे का प्रस्ताव किया गया है।

ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण के लिए विनियामकीय ढांचा

I.11 ऋण उत्पादों के वेब-एग्रीगेटर (डब्ल्यूएएलपी) एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कई उधारदाताओं से ऋण प्रस्तावों का एकत्रीकरण करते हैं जो उधारकर्ताओं को ऋण लेने के लिए तुलना करने और सर्वोत्तम उपलब्ध विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। डिजिटल ऋण संबंधी कार्यसमूह (डब्ल्यूजीडीएल) की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा दी जाने वाली ऋण एकत्रीकरण सेवाओं को एक व्यापक विनियामकीय ढांचे के अंतर्गत लाया जाए। यह ढांचा डब्ल्यूएएलपी के परिचालन में पारदर्शिता बढ़ाने, ग्राहक केंद्रीयता बढ़ाने और उधारकर्ताओं को संसूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

I.12 बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) में संशोधन ने रिज़र्व बैंक को सहकारी बैंकों के मामलों में विनियमन और पर्यवेक्षण को बेहतर बनने का अधिकार दिया। रिज़र्व बैंक ने यूसीबी में ठोस कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख की नियुक्ति शामिल है। शहरी सहकारी बैंकों में जहां अभिशासन संबंधी मुद्दे थे, वहां यूसीबी की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने उन बोर्डों में अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की है।

I.13 वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण संबंधी अक्तूबर 2022 में जारी दिशा-निर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने से कुछ हद तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन में भिन्नता की समस्या का समाधान हो गया है। आरक्षित निधियों से अंतरण/विनियोजन और जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संकेंद्रण के संबंध में प्रकटीकरण के दिशा-निर्देशों से यूसीबी द्वारा प्रकाशित वित्तीय विवरणियों में पारदर्शिता आई है। रिज़र्व बैंक की विनियामकीय कार्रवाइयों का उद्देश्य कमजोर यूसीबी को जल्दी से स्वस्थ करना है और यदि इन प्रयासों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो उन्हें यथासंभव गैर-विघटनकारी तरीके से हल करना है। ये कार्रवाइयां, कुशल और भरोसेमंद वित्तीय मध्यस्थ के रूप में यूसीबी में जनता के विश्वास को स्थापित और गहरा करेंगी।

I.14 मार्च 2022 में यूसीबी के लिए शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन पर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। सहकारी बैंकों के लिए पूंजी निधि जुटाने पर दिशानिर्देशों के दूसरे चरण को जारी करने की जांच करने के लिए एक कार्य-समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया था, जिसमें रिज़र्व बैंक के अधिकारी और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है।

I.15 अब तक हुई प्रगति के बावजूद, सहकारी क्षेत्र को कुछ अंतर्निहित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों के बहुत लंबे और निरंतर कार्यकाल को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, ताकि बोर्ड के कामकाज पर अनुचित प्रभाव डाले जाने वाले निहित स्वार्थों से बचा जा सके और नए निदेशकों को शामिल करके बोर्ड में नए विचारों और दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके। एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति का अभाव कुछ यूसीबी को बाहरी और आंतरिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। कुछ शहरी सहकारी बैंकों में अनुपालन की कमी की संस्कृति प्रचलित है और यह उनके कुछ कार्य-क्षेत्रों में निरंतर अनियमितताओं में परिलक्षित होती है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और अन्य महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी और डेटाबेस कार्यों के प्रबंधन के लिए कुशल कर्मियों की अनुपलब्धता आमतौर पर यूसीबी के लिए बाधा होती है। नतीजतन, इन महत्वपूर्ण कार्यों को आमतौर पर आउटसोर्स किया जाता है जिससे उनके सामने आउटसोर्सिंग जोखिम बना रहता है। ये बैंक साइबर हमलों को रोकने, उनका पता लगाने, प्रति-कार्रवाई करने और उससे उबरने के लिए कम तैयार हैं। ट्रेजरी, साख पत्र, फॉरेक्स और धन-शोधन निवारक समाधानों जैसे विभिन्न मॉड्यूल का कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकरण न होना पर्यवेक्षी चिंता का कारण रहा है और इसकी व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

I.16 महामारी के बाद की अवधि में एनबीएफसी क्षेत्र के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार देखा गया। इस क्षेत्र की समग्र मजबूत स्थिति के बावजूद, कुछ चिंताएं बनी हुई हैं।

बैंकों और एनबीएफसी का परस्पर संबंध

I.17 वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, बैंकों और गैर-बैंकों के बीच परस्पर संबंध पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली से निधि के बड़े निवल उधारकर्ता हैं, जिनका बैंकों को सर्वाधिक एक्सपोज़र है। कई एनबीएफसी एक साथ कई बैंकों के साथ उधार संबंध बनाए रखती हैं। बैंक उनके डिबेंचर और वाणिज्यिक

पत्रों के प्रमुख ग्राहक भी हैं। इस तरह के संकेंद्रित संबंध संक्रामक जोखिम पैदा कर सकते हैं। हालांकि बैंक अच्छी तरह पूंजीकृत हैं, उन्हें एनबीएफसी में अपने निवेश का लगातार मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और साथ ही कई बैंकों के साथ व्यक्तिगत एनबीएफसी के एक्सपोजर का भी मूल्यांकन करना आवश्यक है। एनबीएफसी को अपनी ओर से अपने निधि स्रोतों को व्यापक आधार देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बैंक निधि पर अति-निर्भरता को कम करना चाहिए।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी (जी-एनबीएफसी)

I.18 सरकार की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उनके बढ़ते आकार और वित्त पोषण के कारण, जी-एनबीएफसी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जी-एनबीएफसी के शीर्ष 50 एक्सपोजर ₹7.8 लाख करोड़ रुपये के हैं, जो एनबीएफसी क्षेत्र के कुल कॉरपोरेट क्रेडिट का लगभग 40 प्रतिशत है, जो संकेंद्रण जोखिम की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, ये सभी 50 एक्सपोजर बिजली क्षेत्र के लिए थे, जो कई अंतर्निहित समस्याओं का सामना कर रहा है।

I.19 जी-एनबीएफसी बढ़ते प्रणालीगत महत्व को देखते हुए, एनबीएफसी के लिए लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे को जी-एनबीएफसी (बेस लेयर को छोड़कर) तक विस्तारित किया गया है। यह ढांचा 1 अक्तूबर 2024 से 31 मार्च 2024 की लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट या उसके बाद की रिपोर्ट के आधार पर प्रभावी होगा। इससे इन इकाइयों के पर्यवेक्षण को मजबूत करने और उनके द्वारा समय पर सुधार सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

सूक्ष्म वित्त एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई)

I.20 चूंकि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (एमएफआई) हाशिए पर खड़े ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करती हैं, इसलिए ऋण देते समय उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता पर विचार करने की आवश्यकता है। ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त किए जाने से कुछ एनबीएफसी-एमएफआई अपेक्षाकृत अधिक निवल ब्याज मार्जिन का लाभ उठाते दिख रहे हैं। इसलिए सूक्ष्म वित्त ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्हें प्रदान किए गए लचीलेपन का उपयोग पारदर्शी ब्याज दर निर्धारण प्रक्रियाओं के माध्यम से विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए।

लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

I.21 एसएफबी कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, कई एसएफबी में कम चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमा है और थोक सावधि जमा पर उनकी अधिक निर्भरता है, जो अक्सर उच्च दरों पर, खास कर सहकारी बैंकों से, प्राप्त की जाती है। इससे यह दिखाई पड़ता है कि सहकारी बैंकों के साथ एसएफबी का उच्च स्तर का परस्पर संबंध है। ऐसे में सहकारी बैंकों को किसी प्रकार का आघात लगने पर उससे एसएफबी प्रभावित होने की संभावना है।

I.22 कुछ इकाइयां, जो पहले एनबीएफसी-एमएफआई थीं और बाद में एसएफबी में परिवर्तित हो गईं, ने अपने पहले के व्यवसाय मॉडल को बरकरार रखा है। नतीजतन, उनके पोर्टफोलियो में गैर-जमानती ऋण की हिस्सेदारी अधिक है, जिनमें विशेष रूप से सूक्ष्म वित्त और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण हैं। आस्ति विविधीकरण की यह कमी अक्सर भौगोलिक संकेंद्रण के साथ भी जुड़ी होती है, जिससे बड़ा संकेंद्रण जोखिम पैदा होता है।

I.23 वित्तीय मजबूती और वास्तविक अर्थव्यवस्था में एसएफबी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा पूंजी पर्याप्तता ढांचा आवश्यक है जिसमें एसएफबी के समक्ष आने वाले विभिन्न जोखिमों के लिए उचित समाधानों का प्रावधान हो। एसएफबी के लिए अक्तूबर 2016 में जारी परिचालन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट पूंजी पर्याप्तता ढांचे में कहा गया है कि बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए विवेकपूर्ण ढांचे की जांच की जा रही है और संबंधित अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इस पृष्ठभूमि में, लघु वित्त बैंकों के लिए विनियामकीय पूंजी ढांचे की व्यापक समीक्षा विचाराधीन है।

ग्राहक सेवा

I.24 ग्राहक संरक्षा का एक प्रमुख तत्व उन्हें एक कुशल, त्वरित और किफायती शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। लेकिन, ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान प्रदान करने के लिए बैंकों के प्रयास प्रौद्योगिकी और उत्पादों की तेज गति के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं। बैंक बोर्डों और शीर्ष अधिकारियों को शिकायतों पर केवल निपटान समय (टीएटी)

और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की निगरानी करने के बजाय शिकायत निवारण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आरई को अपनी सेवाओं, उत्पादों और परिचालन में अधिक सहानुभूति लाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ नागरिकों, विशेष जरूरतों वाले लोगों और तकनीक की कम समझ रखने वाले लोगों को सुरक्षित और अनुकूल तकनीक-बैंकिंग प्रदान करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके एक्सेस पॉइंट - शाखाएं, वेबसाइट और ऐप - उपयोगकर्ता के अनुकूल हों और विशेष जरूरतों वाले ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हों।

भुगतान और निपटान प्रणाली

I.25 भुगतान विजन 2025 के अनुसरण में भुगतान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक हितधारक परामर्श चल रहे हैं, जिसमें वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और संदर्भ-आधारित भुगतान के लिए ढांचे की सुविधा और इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन व्यापारी भुगतान प्रसंस्करण के लिए एक भुगतान प्रणाली बनाना शामिल है। ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए अलग से अनुदेश जारी करने की योजना है।

निकट क्षेत्र संचार (एनएफसी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ऑफ़लाइन लेनदेन

I.26 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2022 में ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान की अनुमति देने के अनुदेश जारी किए थे। इस ढांचे के आधार पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लाइट विकसित किए गए थे। इसके अलावा अब यूपीआई लाइट एक्स भी लॉन्च किया गया है जो यूपीआई प्रणाली के माध्यम से धन के अंतरण के लिए एनएफसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह सुविधा उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगी जहां इंटरनेट / दूरसंचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं है। यह अस्वीकृत लेनदेन की संख्या में कमी लाएगा और गति भी सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, एनसीएमसी, जो एनएफसी प्रौद्योगिकी का भी उपयोग करता है, का उपयोग विभिन्न ट्रांजिट ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है।

संवादात्मक भुगतान (कन्वर्जेशनल पेमेंट्स)

I.27 चूंकि संवादात्मक अनुदेशों में यूपीआई प्रणाली के उपयोग और पहुंच में आसानी बढ़ाने की अपार क्षमता है, इसलिए रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को उन्हें पेश करने की अनुमति दी। यूपीआई में संवादात्मक भुगतान उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित वातावरण में लेनदेन शुरू करने और पूरा करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित प्रणाली के साथ जुड़ने में सक्षम करेगा। यह माध्यम स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित यूपीआई, दोनों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा शुरू में हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध होगी और बाद में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

सिंगल-ब्लॉक-और-मल्टीपल-डेबिट के साथ प्रोसेसिंग मैंडेट

I.28 यूपीआई में क्षमताओं को बढ़ाया गया है ताकि ग्राहक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अपने बैंक खातों में धन को अवरुद्ध करके व्यापारियों को भुगतान करने के लिए मैंडेट बना सकें, जिसे आवश्यकतानुसार डेबिट किया जा सकता है। यह द्वितीयक पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद के साथ-साथ रिज़र्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट योजना और विभिन्न ई-कॉमर्स लेनदेन का उपयोग करके सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए भी सहायक होगा। यह लेनदेन में उच्च स्तर के विश्वास का निर्माण करेगा क्योंकि व्यापारियों को समय पर भुगतान का आश्वासन दिया जाएगा, जबकि निधि वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक सुपुर्दगी तक ग्राहक के खाते में रहती है।

नव प्रौद्योगिकी अंगीकरण अवसर और चुनौतियां

I.29 नई प्रौद्योगिकी अपनाने से बैंकों और गैर-बैंकों को अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने, खर्चों को कम करने और जोखिम एक्सपोज़र को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह बैंकों को अपने ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकियां बैंकिंग परिचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं। तथापि, इसके साथ धोखाधड़ी और

डेटा अतिक्रमण के जोखिम भी बढ़ गए हैं। इन खतरों से प्रणाली की रक्षा के लिए विनियामकों, बैंकों और ग्राहकों सहित सभी हितधारकों द्वारा ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। अपनी ओर से रिज़र्व बैंक नवाचारों को बाधित किए बिना ग्राहकों की सुरक्षा के लिए विनियमों को अद्यतन करने का प्रयास कर रहा है।

साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

I.30 भुगतान प्रणालियों के प्रणालीगत महत्व को देखते हुए, मौजूदा और आगामी खतरों के खिलाफ भुगतान प्रणालियों को समुत्थानशील रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने जून 2023 में भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेशों के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। मसौदा निदेशों में साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए अभिशासन तंत्र शामिल हैं, और वे आधारभूत सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट करते हैं।

मॉडल-आधारित उधार

I.31 फिनटेक के साथ बैंकों और एनबीएफसी के बढ़ते गठजोड़ ने मॉडल-आधारित ऋण की शुरुआत की सुविधा प्रदान की है। लेकिन बैंकों और एनबीएफसी को पूर्व-निर्धारित एल्गोरिदम पर पूरी तरह से भरोसा करने में सावधान रहने की आवश्यकता है, जिस पर मॉडल संचालित होते हैं। ये मॉडल मजबूत होने चाहिए और समय-समय पर उनकी समुत्थानशीलता का परीक्षण किया जाना चाहिए। सूचना अंतराल के कारण सिस्टम में किसी भी अनुचित जोखिम निर्माण के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है, जो अंडरराइटिंग मानकों को कमजोर कर सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई / एमएल)

I.32 वित्त क्षेत्र में एआई/एमएल का तेजी से होता जा रहा प्रयोग दक्षता लाभ को बढ़ावा दे रहा है, ग्राहक इंटरफेस को फिर से परिभाषित कर रहा है, पूर्वानुमान सटीकता में वृद्धि कर रहा है, और जोखिम प्रबंधन और अनुपालन में सुधार कर रहा है। तथापि, ये प्रगति एआई / एमएल प्रणालियों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह दोषों (बायस) और उनके परिणामों में पारदर्शिता की कमी से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम भी साथ लाती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी में संभावित रूप से वित्तीय स्थिरता को कम करने में सक्षम प्रणालीगत जोखिमों के नए स्रोत और संचरण चैनल विद्यमान हैं। इसलिए, आरई की क्षमता को मजबूत करके और निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा निगरानी करके, प्रासंगिक कानूनी और विनियामकीय ढांचे को तैयार / अद्यतन करके, संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके और उपभोक्ता शिक्षण का विस्तार करके लाभ और जोखिम के बीच संतुलन बनाना अनिवार्य है।

I.33 रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि अंडरराइटिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एल्गोरिथम व्यापक, सटीक और विविध आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए ताकि किसी भी पूर्वग्रह दोष को दूर किया जा सके। एल्गोरिथ्म न्यूनतम अंडरराइटिंग मानकों और संभावित विभेदन कारकों को इंगित करने के लिए लेखा-परीक्षा करने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा, उधारदाताओं को एथिकल एआई को अपनाना चाहिए जो ग्राहकों के हितों की रक्षा पर केंद्रित हो और पारदर्शिता, समावेशन, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, विश्वसनीयता, सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ावा देती हो।

फिनटेक रिपॉजिटरी की स्थापना

I.34 एक समुत्थानशील फिनटेक क्षेत्र सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विनियामकों और हितधारकों को फिनटेक संस्थाओं के संबंध में प्रासंगिक और अद्यतन जानकारी होनी चाहिए, जिसमें उनकी गतिविधियों की प्रकृति भी शामिल है। इसलिए फिनटेक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रिपॉजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें उनकी गतिविधियों, उत्पादों के प्रकार, प्रौद्योगिकी स्टैक और वित्तीय जानकारी शामिल हैं। फिनटेक को रिपॉजिटरी को स्वैच्छिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उचित नीतिगत दृष्टिकोण तैयार करने में सहायता करेगा। इस रिपॉजिटरी को रिज़र्व बैंक नवोन्मेष केंद्र द्वारा अप्रैल 2024 या उससे पहले चालू किया जाएगा।

नियोजित पर्यवेक्षी नीतियां

I.35 उभरती प्रौद्योगिकी और साइबर जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, पर्यवेक्षी नीतियों को वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से डिजाइन किया जा रहा है।

I.36 मौजूदा दिशानिर्देशों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ-साथ स्तर IV की डिजिटल डेप्थ वाले शहरी सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे साइबर जोखिमों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा प्रचालन केंद्र (सी-एसओसी) स्थापित करें। हालांकि, संगठन विशिष्ट होने के नाते, वे क्षेत्र-व्यापी आम खतरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इन संभावित क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों से निपटने के लिए एक क्षेत्रवार एसओसी (एसएसओसी) की परिकल्पना की गई है। पर्यवेक्षित संस्थाओं के विभिन्न एसओसी से प्राप्त घटनाओं/लॉग/प्रसंगों के सहसंबंध के माध्यम से, एसएसओसी समग्र पारितंत्र में बेहतर सटीकता और स्थिरता के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना प्रदान करेगा। साइबर खतरों की निगरानी और विश्लेषण को केंद्रीकृत करके, यह क्षेत्र तेजी से उभरते हमले के स्वरूपों का सामना कर सकेगा।

I.37 प्रणालीगत जोखिम तब उत्पन्न हो सकते हैं जब विभिन्न आरई सेवाएं प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष की एक छोटी संख्या पर निर्भर होते हैं। संकेंद्रण जोखिम का आकलन करने के लिए, एससीबी से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं को मैप करने के लिए एक व्यापक कवायद शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया के आधार पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के तत्वावधान में बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं की संयुक्त लेखा परीक्षा का प्रस्ताव किया जा रहा है। ये लेखा परीक्षा विक्रेताओं का व्यापक और मानकीकृत मूल्यांकन सुनिश्चित करेंगे।

I.38 बड़ी संख्या में छोटे यूसीबी को अपने भुगतान चैनलों को लक्षित करने वाले जटिलतर साइबर हमलों का सामना करना पड़ा है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल (सीईआरटी-इन) के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों के माध्यम से चुनिंदा यूसीबी में पर्यवेक्षी अनुदेशों के कार्यान्वयन में अंतर का आकलन करने के लिए एक कवायद आयोजित की गई थी। इस कवायद में चरणबद्ध तरीके से भुगतान प्रणाली इंटरफेस वाले सभी यूसीबी को शामिल किया जाएगा। साइबर सुरक्षा तैयारियों में कमियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यूसीबी, भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते समय, मजबूत सुरक्षा उपाय बनाए रखते हैं।

समग्र मूल्यांकन

I.39 भारतीय बैंकिंग प्रणाली और एनबीएफसी उच्च पूंजी अनुपात, आस्ति गुणवत्ता की मजबूती और मजबूत आय वृद्धि के साथ मजबूत और समुत्थानशील बनी हुई हैं। बैंकों और एनबीएफसी के बीच बढ़ते परस्पर संबंधों को देखते हुए, एनबीएफसी को अपने निधिगत स्रोतों को व्यापक आधार देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बैंक निधि पर अति-निर्भरता को कम करना चाहिए। बैंकों और गैर बैंकों, दोनों को अपनी ग्राहक सेवाओं में अधिक सहानुभूति लाने की आवश्यकता है। बैंकिंग प्रणाली और भुगतान प्रणाली को साइबर खतरों से उत्पन्न धोखाधड़ी और डेटा उल्लंघनों के जोखिमों से बचाने के लिए सभी हितधारकों द्वारा ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, बैंकों और एनबीएफसी को भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मजबूत अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से अपने तुलनपत्रों को और मजबूत करने की आवश्यकता है।